ing the new shares as premiums are fixed on the basis of the real value of the assets including the immovable properties. I would also like to know whether the Covernment has given instructions in this regard. I hope the hou. Minister wiH enlighten us on these points.

SHRI MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, I am not an expert in valuation of the shares but I would respectfully submit, as a layman, that if there is property the bank is occupying, there is no chance of that property ever being sold by the bank; whether it influences the decisions with regard to the premium, I really do not know. As of now, the Government does not propose to instruct the banks to do anything specifically in this matter.

MR. CHAIRMAN: Question No. 185. Shri Bapu Kaldate.

Improving the Power Distribution System

*185. DR BAPL KALDATE :t

SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government have critically analysed the ills in the present system of power distirbution in urban and rural areas besides shortages and poor quality of supply resulting in regional imbalances io development;

(b) whether Government have also examined the question of decentralisation and privatisation as an alternative way of power distribution to improve the situation; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF POWER (SHRI N.K.P. SALVE): (a) to (c) A statement Ls laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. Overall gap between demand and supply of power, financial constraints in augmenting generation, transmission and distribution capacity, large scale expansion of urban systems and rural electrification with weak and inadequate sub-transmission and distribution system, too many tarnsformation stages, inadequate maintenance, pilferage and theft of energy, and poor financial position of the State Electricity Boards are some of the reasons for the ills of the present power system of the country.

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Bapu Kal-(tato

(b) and (c) In the background of paucity of funds with Cential and Mate Governments/undertakings and acute power shortage, Government decided to permit private sector participation in power sector for bringing in additionality of resources for capacity addition in electricity generation, supply and distribution. The details of incentives/policy guidelines to encourage greater private sector participation is given in the enclosed Statement-I

Statement-I

IMPROVING THE POV/ER DISTRIBUTION SYSTEM

Incentives/Policy guidelines to encourage greater private sector participation in the electricity generation and distribution.

— Private Sector can set up thermal projects (coal/ gas) and hydel projects and wind/solar energy project of any size.

— Electricity Projects where tlie total outlay does not exceed Rs. 25 crores need not be submitted to the Central Electricity Authority for concurrence.

— Private Sector companies can set up enterprises to operate either as licensees or as generating companies.

— All private companies entering the Electricity Sector hereafter will be ailowed a debt-equity ratio upto 4:1,

• - Promoter's contribution should be at least 11% of the total outlay.

— To ensure that private entrepreneurs bring in additionality of resources to the sector, not less than 60% of the total outlay for the project must come from sources other than Public Financial Institutions.

— Upto hundred per cent (100%) foreign equity participation can be permitted for projects set up by foreign private investors.

— The condition of dividend balancing by export earnings which is normally being applied to cases of foreign investment upto 51% equity will not be applicable to foreign investments in the power sector.

— The rates for depreciation in respect of assets have been liberalised.

— With the approval of the Government, import of equipment for power projects will also permitted in cases where foreign supplier(s) or agency (ies) extended concessional credit.

— The customs duty for import of power equipment has been reduced to 20% and this rate has also been extended to machinery required for modernisation and renovation of power plants.

— A five year tax holiday has been allowed in respect of profits and

gains of new industrial undertakings set up anywhere in India for either generation or generation and distribution of power. The five year tax holiday will begin from the year of generation of power.

— The excise duty on a large number of capital goods and instruments in the power sector has been reduced to a uniform lower rate of 5%.

— Upto 16% return on the foreign equity included in the tariff can be provided in the respective foreign currency.

— Fixed costs including 16% Return On Equity (ROE) can be recovered at 68.5% PLF. Attractive incentives are prescribed for performance beyond this PLF in the form of additional ROE (upto 0.7%) for each 1% rise in PLF.

— Flexibility has been allowed in including insurance charges in the project cost.

— Government of India may consider extending a counter guarantee for the payment obligations of State Electricity Boards to the private power companies on the specific request of the concerned State Government subject to certain terms and conditions.

The specific incentives for Licensees are:

— Licensees of longer duration of 30 years in the first instance and subsequent renewals of 20 years instead of 20 and 10 years respectively as it was before.

— Higher rate of return of 5% in place of the previous 2% above the RBI rate.

— Capitalisation of Interest During Construction (IDC) at actual cost (for expansion projects also) as against 1% over RBI rate as it was before.

— Special appropriations to meet debt redemption obligations.

MR. CHAIRMAN: First supplementary.

डा० बापू कालदाते : सभापति महोदय, जहां तक ऊर्जा की बीमारियों का निदान है, वहां तक तो कई बातें आपने ठीक रखी है, लेकिन निदान के साथ-साथ चिकित्सा की भी आवश्यकता होती है । आपने निदान तो बहुत कर दिए है कि यह डिस्ट्रिब्यूशन की कुछ गलतियां हैं, फाइनेन्शियल कन्सट्रेंट है, एग्जम्पशन है, एक्सटेंशन के लिए पैसा नहीं है । कमजोरियां वगैरह सब ठीक हैं । इसके साथ जो दूसरा सवाल हमने जोड़ा है कि इस दिशा में आप रिसोर्सेज की हद तक प्राइवेटाइजेशन की क्या बात करते हैं ? मैं पहले ही बात साफ कर देना चाहता हूं कि सिर्फ निजीकरण इन बीमारियों का रामबाण उपाय नहीं है । It is not apanacea for all the diseases and ills that we are having.

अब मैं आपसे एक ही स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि यह पता है कि जो सबसे बुरी हालत इस सारे सिस्टम में है वह है आपके जो बोर्ड हैं, एस० ई०बी०, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एक तो इनके पास पैसे नहीं हैं या जिस ढंग से वह मुनाफे में नहीं चला सकते और इसके लिए उनकी वर्किंग केपिटल की हालत भी बहुत बुरी है, यहां तक कि कुछ एस० ई०बी० ज्यादा बैंकरप्ट हो रहे है । तो इसके रि-स्ट्रक्चरिंग की बात एक होगी और दूसरी बात यह होगी कि आमतौर पर कुछ लोग यह कहते रहे हैं कि दाम बढ़ाने चाहिए, रेट बढ़ाने की आवश्यकता है । तो एक तो रि-स्ट्रक्चरिंग के बारे में और दाम बढ़ाने की जो बात चल रही है उसके बारे में सरकार किस ढंग से सोच रही है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : यहां तक प्रश्न का सवाल है,... **(व्यवधान)**...

डा० बापू कालदाते : प्रश्न का सवाल नहीं, प्रश्न का उत्तर है । प्रश्न का सवाल कहां से होगा ?... **(व्यवधान)**...

श्री एन० के० पी० साल्वे : यहां तक प्रश्न में आपने जो फरमाया है । ...**(व्यवधान)**...

SHRI BAPU KALDATE: You can carry on in English. I have no problem.

श्री एन० पी० के० साल्वे : थोड़ी हिंदी बोल लेता हूँ ।...**(व्यवधान)**...

डा० बापू कालदाते : अच्छा बोल दीजिए । नागपुर के हैं आप, पुराने मध्यप्रदेशीय हैं ।

श्री एन० के० पी० साल्वे : नहीं हिंदी थोड़ी बोल लेता हूँ, आपकी जितनी महीन और साफ न आती हो, थोड़ी तो बोल लेता हूँ । राष्ट्रभाषा है हमारी । सभापति जी, मेरा निवेदन यह था कि जो बात कही है प्रश्न में माननीय बापू कालदाते जी ने, बहुत माकूल है, बहुत बजा है ।

सवाल यह उठता है कि रि-स्ट्रक्चरिंग का और फाइनैंशियल रिसोर्सिसिज का, जिसके लिए टेरिफ बढ़ाने की बात कही है, यह मसाइल यह प्रश्न स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आता है और इसलिए कुछ मजबूरियां हैं हमारी । मगर यह नहीं की हम हाथ पर हाथ धरे बैठ हुए हैं, लगातार, मुतवातिर कोशिशें कर रहे हैं कि जब तक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की फंक्शनिंग ठीक नहीं होगी, हमारे ऊर्जा क्षेत्र में किसी भी तरह का सुधार नहीं आ सकता । क्युमूलेटिव लॉसिस 35 हजार करोड़ के हैं । 1993-94 में पांच हजार करोड़ का लॉस हुआ है । इस तरह की घाटे की स्थिति में हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अगर

चलेंगे तो उनका फिजिकल परफारमेंस और फाइनैंशियल परफारमेंस हमेशा गड़बड़ी का रहेगा और गड़बड़ी का रहा है और उसके परिणामस्वरूप पूरे ऊर्जा क्षेत्र को सफर करना पड़ रहा है ।

जहां तक रि-स्ट्रक्चरिंग का सवाल है, हम लोगों ने जनवरी, 1993 में स्टेट पावर मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस की थी और उसमें कुछ फैसले लिए थे । उसमें यह बहुत अहम फैसला लिया था कि प्लांट लोड फास्टर बढ़ाया जाए, ट्रांसमीशन डिस्ट्रिब्यूशन लॉसिस कम किए जाएं । उसमें यह भी फैसला लिया था कि जहां तक कृषि के क्षेत्र में ऊर्जा की दरों का सवाल है, टेरिफ का सवाल है, वह कम से कम 50 पैसा प्रति किलोवाट अगर हो जाए, अब उस पर कुछ राज्यों ने तो अमल किया है, कुछ राज्यों ने अमल नहीं किया है । अध्यक्ष जी, यह कन्करेंट सब्जेक्ट है । उनका अधिकार, उनकी अथारिटी उतनी है जितनी हमारी है । उनके अधिकार क्षेत्र में हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते । अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो रही है, वह कर रहे हैं, उनके फाइनैंसिस अच्छे हों । फाइनैंशियल पैरामिटर्स और ऑपरेशनल पैरामीटर्स जुटाने की हम कोशिश कर रहे हैं और यह लगातार करते रहेंगे । इस सिलसिले में अगर माननीय सदस्य हमारी कुछ मदद कर सकें तो मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा क्योंकि दिक्कत यह है कि जो दरों का सवाल है, बहुत अहम सवाल है । जो राज्य सरकारें हैं, वह एक नीति निर्धारित करती है अपने लिए कि जहां तक अलग-अलग दायरों का, अलग-अलग एरियाज का, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे एग्रीकल्चरल हो, चाहे डोमेस्टिक हो, एक अलग-अलग रेट हो और उसमें अगर राजनीति आने लगे तो वही होगा जो हो रहा है । यह दरअसल सब मुद्दों का एक मुद्दा है, यह मेरा निवेदन है।

सभापति : सैकिंड सप्लीमेंटरी ।

डा० बापू कालदाते : नहीं । यह पूछ लें ।

श्रीमती कमला सिन्हा : अध्यक्ष जी, मंत्री जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी । मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि यह कन्करेंट सब्जेक्ट है और प्रांतों को इसके बारे में देखना होगा । बात तो सही है लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि क्या यह सही है कि पूर्वी प्रांतों में से, जहां से ऊर्जा का जो रा-मेटीरियल है कोयला, वह ज्यादा तो पूर्वी प्रांतों से, ही आता है, जैसे बिहार । बिहार से 40 प्रतिशत कोयले का उत्पादन होता है और ऊर्जा का उत्पादन दूसरे प्रांतों में है । बिहार तो पावर स्टार्व्ड स्टेट है । उसी तरह से उड़ीसा, बंगाल है, पिछले तीन सालों में इनकी ऊर्जा की खपत गिरी है । तो क्या यह सही है कि पिछले 30—40 सालों में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तहत कारखाने लगाए गए थे, उनका नवीनीकरण नहीं हुआ और केन्द्रीय सरकार ने कोई ऊर्जा का कारखाना वहां लगाया ही नहीं और इसीलिए यह एस०ई०बी० भी बीमार पड़ रहा है और साथ-साथ प्रांत भी पीछे हो रहे है, क्या यह बात सत्य है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : अंशतः सत्य है, अंशतः असत्य है ।

श्रीमती कमला सिन्हा : पूर्णतः सत्य है ।

श्री एन० के० पी० साल्वे : ईस्टर्न सेक्टर में इस्टर्न ग्रिड है । ईस्टर्न ग्रिड में हमने बहुत सारे कारखाने लगाए हैं और ईस्टर्न ग्रिड को और दूसरे ग्रिड के मुकाबले में पर्याप्त पावर दी जा रही है । मगर पहला सवाल जो आपने किया, वह बिल्कुल सत्य है कि जहां कोयला होता है वहां कारखाने लगें, ऐसी कोई नीति अभी नहीं है । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि नयी नीति में हम चाहते हैं कि जहां कोयले की खदानें हों वहां ही कारखाने लगें बल्कि ऊर्जा के कारखाने वहीं लगें । यह बहुत जरूरी है । मैं एक चीज और बता दूं कि इस प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न और है कि सस्ता कोयला मिल जाए तो पावर का जो ट्रांसमिशन है, वह ज्यादा सस्ता पड़ता है । यही मेरा निवेदन है ।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. Now Papers to be laid on the Table of the House—Shri Sukh Ram.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Privatisation of Power Plants in Maharashtra

•183. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal for privatisation of any major power plant in Maharashtra;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the stage at which this proposal stands and by when the final decision is likely to be taken ?

THE MINISTER OF POWER (SHRI N.K.P. SALVE): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

News Coverage for various Political Partie*

♦186. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is definite tilt at present in favour of ruling party in respect of news coverage on Doordarshan and A.I.R, networks;